

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 11 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट))

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष लगातार दादपुर नलवी नहर के मुद्दे पर गुमराह कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष 20 दिसंबर को दिया गया फैसला दादपुर नलवी के बारे में नहीं है। इस 76 पन्नों के फैसले में उच्च न्यायालय ने दादपुर नलवी नहर दोबारा बनाई जाए, ऐसा कहीं नहीं कहा है। विपक्ष अपनी नाकामी छुपाने के लिए तथ्यहीन आरोप लगा रहा है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के महाधिवक्ता की राय पर इस फैसले को लेकर विशेष अनुमति याचिका एस एल पी दायर करने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने कहा कि इस नहर के निर्माण के लिए 2247 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था और उसमें से 190 एकड़ तो सरकारी भूमि थी। उस समय की राज्य सरकार लोगों के विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि अधिकृत ही नहीं कर पाई थी। केवल 830 एकड़ भूमि ही अधिकृत हुई थी। उन्होंने बताया कि 2004-05 में जब यह भूमि अधिकृत की गई तो कोर्ट ने राशि में वृद्धि का आदेश भी दिया जो 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बनती थी। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। रोहतक-गोहाना रोड़ पर पीर बोधी तालाब पर अतिक्रमण के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस तालाब की भूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। यह भूमि वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी। विपक्ष द्वारा इस संबंध में सभी आरोप निराधार हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में 18 संकल्पों को पूरा किया है और 10 संकल्प जल्द ही पूरे होने वाले हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मेवात क्षेत्र में स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़कों के सुदृढीकरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मेवात में विकास को और गति देने के लिए शीघ्र ही मेवात विकास बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज विधानसभा बजट सत्र में

प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे । उन्होंने कहा की वर्ष 2014 से पूर्व मेवात के विकास और वर्ष 2014 के बाद पिछले दस वर्षों में हुए विकास में अंतर साफ दिखाई देता है । मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नूह को आकांक्षी जिला घोषित किया है जिसके तहत जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास पर विशेष रूप से काम किया गया है ।

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि 'मुख्यमंत्री खेत खलिहान सड़क योजना' के तहत अब तक 90 विधानसभा क्षेत्र में 3580 किलोमीटर से अधिक रास्तों को पक्का किया गया है। इस पर 639 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक खेतों के कच्चे रास्तों को पक्का करने का प्रावधान है। श्री पंवार हरियाणा विधानसभा में विधायक उमेद सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि जहां तक चरखी दादरी जिले की बात है इस जिले में 28 किलोमीटर 41 मीटर रास्तों को पक्का करने के लिए अब तक 10 करोड़ 39 लाख 31 हजार रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

करनाल जिले में लिंगानुपात 1 हजार लड़कों की तुलना में 926 का आंकड़ा पार कर गया है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल जिला प्रशासन को लिंगानुपात सुधार में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वर्ष 2014 में जिलों में लिंगानुपात 886 था, वर्ष 2018 में यह अनुपात बढ़कर 934 हुआ, वर्ष 2023 में लिंगानुपात 908 हो गया। गत वर्ष 2024 में लिंगानुपात सुधार होकर 926 का आंकड़ा पार कर गया। कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने तथा लिंगानुपात की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आपकी बेटी-हमारी बेटी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की उप सिविल डॉ सर्जन शीनू शर्मा ने लिंग अनुपात में लड़कियों की संख्या में इजाफा होने की वजह पंजीकरण के बगैर किसी भी सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल के अल्ट्रासाउंड करने पर सख्ती से रोक लगाना है।
